यह कहा जा सकता है कि किसी खास क्षेत्र में ऋण का अभिनियोजन आर्थिक क्रिया कलापों के स्तर, उद्यमवृत्ति कच्चे माल और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता अन्य निवेश के अवसर और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न मदों पर निर्भर करता है।

विवरण

मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार ऋण जमा अनुपात

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	
	ग्रामीण	अर्द्धशहरी
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	45.1	37.7
हरियाणा	60.4	46.3
हिमाचल प्रदेश	31.8	31.5
जम्मू व कश्मीर	21.7	29.5
पंजाब	44.5	33.3
राजस्थान	63.0	44.1
चंडीगढ़	29.5	14.3
दिल्ली	15.0	12.9
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	55.6	36.6
अरुणाचल प्रदेश	13.8	83.9
असम	64.5	36.8
मणिपुर	151.8	118.7
मेघालय	36.0	14.6
मिजोरम	34.8	16.3
नागालैंड	37.3	41.4
त्रिपुरा	98.9	66.2
पूर्वी क्षेत्र	52.0	32.3
बिहार	50.9	32.7
उड़ीसा	79.3	53.8
सिक्किम	23.5	24.6
प० बंगाल	45.8	25.5
अंडमान व नि० द्वीपसमूह	24.5	30.7
मध्य क्षेत्र	47.3	45.8
मध्य प्रदेश	64.0	48.0
उत्तर प्रदेश	42.6	43.7
पश्चिमी क्षेत्र	56.5	49.3
गोवा	17.2	36.8
गुजरात	54.3	53.3
महाराष्ट्र		50.6
दादरा व ना० हवेली	27.6	—
दमन व दीव	14.1	17.8
दक्षिणी क्षेत्र	86.4	52.6
आन्ध्र प्रदेश	94.2	65.6
कर्नाटक	84.3	60.5
केरल	52.0	37.7
तमिलनाडु	96.3	63.9
लक्षद्वीप	9.9	—
पांडिचेरी	44.7	32.1
अखिल भारत	56.9	45.0

उद्योग-रहित जिलों के विकास में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका

865. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उद्योग रहित जिलों के विकास में कोई सहायता नहीं की है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योग-रहित जिलों के विकास में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका को दर्शाने वाला ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिसम्बर 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार अपनी प्रत्यक्ष वित्त योजना के तहत गैर औद्योगिक जिलों में अवस्थित 154 परियोजनाओं को 1914.4 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक गैर औद्योगिक जिलों के उद्योगों को पुनर्वित्त और पुनर्भनाई सहायता के रूप में सहयोग प्रदान करता है।

लघु उद्योगों को बैंक ऋण

866. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों को ऋण देने के संबंध में बैंकों की भूमिका असंतोषजनक रही है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या बैंक, उद्योगों को उनके वर्गीकरण के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन वर्गीकृत उद्योगों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नायक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लघु उद्योग क्षेत्र कमजोर पूंजी आधार, पूंजी बाजार में बहुत कम पहुंच और प्रबंधकीय संगठनात्मक और वित्तीय कुशलता की कमी से ग्रस्त है। बैंकों के कार्यशील पूंजी के प्रोफाइल से पता चलता है कि लघु उद्योग क्षेत्र के मामले में उत्पादन के मुकाबले में कार्यशील पूंजी का स्तर बड़े एककों की तुलना में कम है। लघु उद्योग क्षेत्र में भी ग्रामीण उद्योगों तथा अति लघु उद्योगों के उत्पादन के मुकाबले में कार्यशील पूंजी का स्तर और भी कम है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में ग्रामीण उद्योगों अति लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योगों को इसी क्रम में वरीयता प्रदान करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि जिन ग्रामीण उद्योगों, लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योगों की बैंकिंग प्रणाली से कुल मिलाकर निधि पर आधारित कार्यशील पूंजी सीमा एक करोड़ रुपये तक है, उन्हें कार्यशील पूंजी दी जाए जिसका आकलन नए और वर्तमान एककों के वार्षिक अनुमानित टर्नओवर के 20% पर किया जाए।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर ऋण देने के बारे में बैंकों को कोई हिदायतें नहीं दी हैं।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

Increase in Inflation Rate

867. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what steps have been taken by Government to contain the ever increasing growth rate of inflation;

(b) what are the parameters with which inflationary trend is determined;

(c) whether Government are likely to achieve zero growth rate of inflation in the near future;

(d) how much unaccounted money was unearthed by income-tax raids at all levels in the country in the year 1990-91 onwards, till date; and

(e) whether Government propose capital punishment for economic offenders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) In order to ensure adequate availability of essential commodities at reasonable prices, a constant vigil is kept on prices for the purpose of supply management in respect of 12 out of 30 essential commodities namely, rice, wheat, sugar, vanaspati, groundnut oil, mustard oil, gram dal, tur dal, onion, potato, salt and tea. At the macro level sustained efforts at containing fiscal deficit is the major policy initiative for controlling inflation.

(b) The trends in fiscal deficit and money supply, rate of growth in industrial and agricultural production and the policy on farm support prices are some of the parameters influencing trends in inflation.

(c) The Government's immediate objective is to achieve faster economic growth rather than a zero inflation rate.

(d) The details of seizure of unaccounted assests and disclosure of concealed incomes under Section 132 (4) of the Income-Tax Act, in course of searches conducted by the Income-tax Department during the period from the financial year 1990-91 to 1993-94 (Upto January, 1994), are as under: